

प्रिय,

एनएचएममलब्याल,
प्रमुख राशि,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राज्य विभाग

देहरादून: दिनांक 27 मार्च, 2008

विषय: बिरला इन्स्टीट्यूशन को शिक्षण संस्थान (नर्सरी से कक्षा 8 तक) की स्थापना हेतु तहसील किछा के ग्राम लालपुर में कुल 4.465 हे० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-508/सात-स०न०३०/2008 दिनांक 16 जनवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बिरला इन्स्टीट्यूशन को शिक्षण संस्थान (नर्सरी से कक्षा 8 तक) की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र०) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं संपन्नतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत तहसील किछा के ग्राम लालपुर में कुल 4.465 हे० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- कंटा धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- कंटा धारा या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि दण्डक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों का भी ग्रहण कर सकेगा।

3- कंटा द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के मंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

- (2)



गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कचरा फैलाया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-187 के परिणाम लागू होंगे।

जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कचरे से पूर्ण सम्पन्नित जलाशयों से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असकम्पीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

स्थापित किये जाने वाले संस्थान में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवाप्रयोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

समश्लेष शर्तों/प्रतिबंधों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे कारण उचित समझा जाय, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन०एल०एल०पल०बाल)
प्रमुख सचिव।

संस्था एवं तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
- श्री आर०एल०एल०खोटा, बिरला इन्स्टिट्यूशन, 9/1 आर०एन०मुखर्जी रोड, 7वीं तल, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।
- निदेशक, एन०आइ०सी० उत्तरांचल सचिवालय।
- मार्ग फाइल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।
9✓